वे केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार स्थापित किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं—

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/ आदिवासी क्षेत्र
उप केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

1991 की जनगणना के अनुसार इन सुविधाओं की अपेक्षित तथा कार्यरत स्थिति इस प्रकार है—

स्वास्थ्य केन्द्र	अपेक्षित	दिसम्बर, 95 को कार्यरत
उप केन्द्र	134105	132285
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	22351	21802
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5588	2401

इस अन्तर को जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रों द्वारा अथवा मौजूदा केन्द्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था से सेवाओं का विस्तार करके दूर करने का प्रस्ताव है। यह कार्य 9वीं योजना में किया जाएगा।

(ख) सरकार ग्रामीण जनसंख्या को उल्लिखित स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले निवारक, उपचारात्मक, परिवार कल्याण सेवाएं तथा टीकाकरण सुविधाएं प्रदान कर रही है।

Product diversification programme of Haldia Refinery

*40. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any product diversification programme is being planned by Haldia Refinery of IOC, if so, the details thereof;

(b) whether any feasibility report has been prepared and examined by IOC for utilising the existing facilities of the Fertilizer Project of HFC, Haldia; and

(c) if so, whether the same involves production of Chemicals/Fertilizer by IOC, other than utilisation of infrastruc-tural facilities of Haldia Project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T. R. BAALU): (a) As a part of product diversification, Microcrystallinc wax production/despatch facilities are under implementation by IOC at Haldia Refinery. The project estimated to cost Rs. 35 crores is scheduled to be mechanically completed by April, 1999.

(b) and (c) IOC is exploring the feasibility of utilising some of the idle facilities of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. at Haldia.

गांवों का विद्युतीकरण

39. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने राजस्व ग्राम हैं और ऐसे कितने राजस्व ग्राम विद्युत विहीन हैं; और

(ख) इन ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) 31.3.1996 को उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में अभी 80,927 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ख) शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों में से अधिकांश दूरस्थ, दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनके विद्युतीकरण के लिए बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों से शेष गांवों का विद्युतीकरण पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु तथा आवश्यक कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।